ट्रैक्टर (वितरण) नियंत्रण आदेश, 1971 को सुदृढ़ बनाया जाना

1700. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टर विक्रेता किसानों द्वारा पंजीकरण के समय जमा कराई जाने वाली धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देते, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों द्वारा जमा कराई जाने वाली धनराशि पर ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक्टर (वितरण) नियंत्रण आदेश, 1971 के अन्तर्गत कोई नियम बनाने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही : (क) बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि स्वीकार करना ग्राहक एवं कम्पनी के बीच एक करार संबंधी दायित्व समझा जाता है

(ख) जी, नहीं।

Closure of small scale units

1701. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 10 per cent of small scale units have been closed down in the country for various reasons; and

(b) if so, the total number of units closed since the announcement of new economic policy; and the number of workers thus losing employment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO & RURAL INDUSTRIES) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIAN) : (a) As per results revealed by the Second All India Census of Small Scale Industrial Units conducted by the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries) covering units registered and falling under the purview of Small Industries Development Organisation (SIDO) with reference to year 1987-88, 31% units were found closed over a span of 15 years.

(b) Since the announcement of new Economic Policy no Study/Survey has been conducted regarding closed units. As such information regarding number of closed units and number of workers losing employment is not avaialble.

Seizure of Files pertaining to PSUs by C.B.I.

1702. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the CBI had recently seized certain files pertaining to disinvestment in the Public Sector Undertakings;

(b) if so, what are the issues under investigation by the CBI;

(c) what is the outcome of the investigations; and

(d) what is the affect of the seizure of the files on the new target for realisation through sales of Government shares in PSUs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) CBI obtained the files regarding disinvestment of Public Sector Undertakings shares for examination. The outcome of the eramniation of these files has not been made known to the Government.

(d) Does not arise in view of the above.

एच०ई०सी० और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में आर्थिक संकट

1703. **श्री गया सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच०ई०सी० हटिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति भी काफी गंभीर है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एच० ई० सी० बेशी जनशक्ति और घटिया कार्य संस्कृति; उच्च ऊपरी खर्चों और अधिक ब्याज भार; कार्यशील पूंजी की कमी तथा असंतुलित क्रयादेश स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारणों से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है।

(ख) भेल को उपभोक्ताओं से अधिक बकाया राशियों के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता

1704. **श्री अजीत जोगी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता बहुत ज्यादा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्य सरकारों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को क्या-क्या साधन उपलब्ध कराए गए हैं, और

(घ) क्या पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के अभाव के कारण यह रूग्णता अपेक्षाकृत अधिक है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1991 के अन्त में मध्य प्रदेश राज्य में लघु क्षेत्र में 17146 औद्योगिक एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 49 औद्योगिक एकक रुग्ण थे।

(ख) बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार औद्योगिक रुग्णता के मुख्य कारण विपणन, तकनीक, श्रम और उत्पादन समस्याओं, प्रबंध की कमियों, बिजली की कमी, मांग की कमी और प्राकृतिक विपत्तियों से संबंधित हैं।

(ग) 1981 (फरवरी, 1982 में संशोधित) में केन्द्र सरकार द्वारा जारी रुग्ण उद्योगों के लिए नीति संबंधी दिशा निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं :—

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक एककों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

(2) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी मानीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि रुग्णता को प्रारम्भिक अवस्था में रोकने हेतु समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

(3) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को अलग अलग रुग्ण एककों के निदान अध्ययन के आधार पर सम्भावित जीव्यक्षम मामलों में पुनरुज्जीवन योजनाएं तैयार करनी चाहिए।

उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अलावा, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन एक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है ताकि रुग्ण और सम्भावित रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाया जा सके और निरोधात्मक, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का शीघ्रता से निर्धारण किया जा सके।